International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 8, August 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य: चुनौतियां और अवसर

डॉ0 केशरी नन्दन मिश्रा

एसोसिएट प्रोफेसर (इतिहास), हेमवती नन्दन बहुगुणा राजकीय पी.जी. कालेज, नैनी, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश, भारत।

सारांश

उच्च शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है। यह पर्याप्त ज्ञान और विशिष्ट कौशल प्रदान करके मनुष्य को सभी पहलुओं में विकसित करने में मदद करता है। यह मानव को उपयोगी मानव संसाधन में परिवर्तित करता है जो देश के समग्र विकास के लिए बहुत आवश्यक है। उच्च शिक्षा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मनुष्य को रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करती है। भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संक्रमण के चरण में है। इसने कुछ खतरनाक मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों को थोपा है।

यह पत्र भारत में उच्च शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य समाज के सभी समूहों के लिए उच्च शिक्षा की पहुंच, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता आदि जैसे विभिन्न मुद्दों की पहचान करना है। माध्यमिक डेटा का उपयोग उच्च शिक्षा के आंकड़े प्रदान करने और उच्च शिक्षा क्षेत्र के मौजूदा परिदृश्य का अवलोकन देने के लिए किया जाता है। यह अध्ययन चुनौतियों की पहचान भी करता है और उच्च शिक्षा क्षेत्र में बाधाओं को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय सुझाता है।

मूल शब्द: उच्च शिक्षा, कौशल, गुणवत्ता, परिदृश्य, आंकड़े, चुनौतियों

प्रस्तावना

उच्च शिक्षा के महत्व को संयुक्त राज्य के पूर्व राष्ट्रपति बैरक ओबामा द्वारा निम्नलिखित शब्दों में स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, "उच्च शिक्षा केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए आरक्षित विलासिता नहीं हो सकती है। यह प्रत्येक परिवार की आर्थिक आवश्यकता है। और हर परिवार को इसे वहन करने में सक्षम होना चाहिए। " उच्च शिक्षा सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास, समानता और न्याय का समर्थन करने के लिए एक दीर्घकालिक सामाजिक निवेश है। 21 वीं सदी में, उच्च शिक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग ज्ञान आधारित समाज के निर्माण के लिए किया जा सकता है।

उच्च शिक्षा: अवधारणाएं और अर्थ-

उच्च शिक्षा शब्द अस्पष्ट प्रकृति का है क्योंकि इसका प्रयोग अलग-अलग लोगों, अलग-अलग देशों और अलग-अलग समय में अलग-अलग तरीकों से किया जाता है। इसलिए, उच्च शिक्षा को परिभाषित करने के लिए कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा और आगे की शिक्षा में विभाजित किया जा सकता है और संयुक्त रूप से, इसे तृतीयक शिक्षा के रूप में जाना जाता है। उच्च शिक्षा योग्यता उच्च डिप्लोमा, फाउंडेशन डिग्री से ऑनर्स डिग्री का अनुमान लगाती है। इन पाठ्यक्रमों को पूरा करने में न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर अधिकतम 4 वर्ष तक का समय लगता है। दूसरी ओर, आगे की शिक्षा स्नातक से ऊपर की डिग्री, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री को संदर्भित करती है। संक्षेप में, तृतीयक शिक्षा का अर्थ है कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा। उच्च माध्यमिक शिक्षा के बाद भारत में उच्च शिक्षा के रूप में जाना जाता है।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 8, August 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य

भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तृतीयक स्तर पर मुख्य शासी निकाय है, जो अपने मानकों को लागू करता है, सरकार को सलाह देता है, और केंद्र और के बीच समन्वय करने में मदद करता है। राज्य। उच्च शिक्षा के लिए प्रमाणन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित 15 स्वायत्त संस्थानों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय और इसके घटक कॉलेज मुख्य संस्थान हैं।

वर्ष 2015-16 के लिए उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) की रिपोर्ट भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों के विभिन्न पहलुओं का वर्गीकरण और प्रतिनिधित्व करती है। इसमें देश के संपूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान शामिल हैं। संस्थानों को 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है; विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्टैंड-अलोन संस्थान। 799 विश्वविद्यालय, 39071 कॉलेज और 11923 स्टैंड अलोन संस्थान हैं। 277 विश्वविद्यालय निजी तौर पर प्रबंधित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 307 विश्वविद्यालय स्थित हैं। 14 विश्वविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं, राजस्थान में 4, तमिलनाडु में 2 और आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 1-1 विश्वविद्यालय हैं। 1 केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 13 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और 1 राज्य निजी मुक्त विश्वविद्यालय के अलावा, 118 दोहरी मोड विश्वविद्यालय हैं, जो दूरस्थ मोड के माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करते हैं और उनमें से अधिकतम (19) तमिलनाडु में स्थित हैं। 459 सामान्य, 101 तकनीकी, 64 कृषि और संबद्ध, 50 चिकित्सा, 20 कानून, 11 संस्कृत और 7 भाषा विश्वविद्यालय हैं। भारत में कॉलेजों की संख्या के मामले में शीर्ष 8 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश हैं। 970 कॉलेजों के साथ कॉलेजों की संख्या के मामले में बैंगलोर जिला शीर्ष पर है, इसके बाद जयपुर 616 कॉलेजों के साथ है। शीर्ष 50 जिलों में लगभग 34% कॉलेज हैं। 60% कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। 11.1% कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। केवल 1.7% कॉलेज ही पीएच.डी. चलाते हैं। कार्यक्रम और 33% कॉलेज स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रम चलाते हैं। 78% कॉलेज निजी तौर पर प्रबंधित हैं; 64% निजी-अनुदानित और 14% निजी सहायता प्राप्त। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 80% से अधिक निजी-गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज हैं और तमिलनाडु में 76% निजी-गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज हैं, जबकि बिहार में

में 13% और असम में केवल 10% निजी-गैर-सहायता प्राप्त कॉलेज हैं। 22% कॉलेजों में नामांकन 100 से कम है और केवल 4.3% कॉलेजों में 3000 से अधिक नामांकन हैं। उच्च शिक्षा में 18.6 मिलियन लड़कों और 1.6 मिलियन लड़कियों के साथ कुल नामांकन 34.6 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। लड़कियों का कुल नामांकन में 46.2% हिस्सा है। भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 24.5% है, जिसकी गणना 18-23 वर्ष के आयु वर्ग के लिए की जाती है। पुरुष आबादी के लिए जीईआर 25.4% है और महिलाओं के लिए यह 23.5% है। अनुसूचित जातियों के लिए, यह 19.9% है और अनुसूचित जनजातियों के लिए, यह 24.5% के राष्ट्रीय जीईआर की तुलना में 14.2% है। लगभग 79.3% छात्र स्नातक स्तर के कार्यक्रम में नामांकित हैं। पीएचडी में 1,26,451 छात्र नामांकित हैं। जो कुल छात्र नामांकन का 0.4 प्रतिशत से भी कम है। शिक्षकों की अनुमानित कुल संख्या 15,18,813 है। जिनमें से आधे से अधिक लगभग 61% पुरुष शिक्षक हैं और 39% महिला शिक्षक हैं। अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 100 पुरुष शिक्षकों पर केवल 64 महिला शिक्षक हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 21 है यदि नियमित नामांकन माना जाता है। पीएच.डी. का हिस्सा छात्र राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय (33%) में सबसे अधिक है, उसके बाद राष्ट्रीय महत्व संस्थान (22%), केंद्रीय विश्वविद्यालय (14%) और डीम्ड विश्वविद्यालय-निजी (12%) है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में छात्राओं की संख्या सबसे कम है, इसके बाद राज्य के निजी मुक्त विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालय-सरकार का स्थान है। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में ऋण अनुदान प्रदान करता है, लेकिन यह उच्च शिक्षा के संस्थानों में समन्वय, सूत्रीकरण और मानकों को बनाए रखने के

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 8, August 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

लिए भी जिम्मेदार है। यूजीसी के अलावा यहां विभिन्न पेशेवर परिषदें हैं जो पाठ्यक्रमों को मान्यता देने, पेशेवर संस्थानों को बढ़ावा देने और स्नातक कार्यक्रमों को अनुदान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) हैं। , मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई), फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी), डेंटिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई), सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी (सीसीएच) और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन (सीसीआईएम) वैधानिक पेशेवर हैं। भारत की परिषदें।

भारत में उच्च शिक्षा में प्रमुख चिंताएं और विचारोत्तेजक उपाय-

1. नवप्रवर्तन का अभाव- कई महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम अद्यतन नहीं है। यह छात्रों को नया ज्ञान और कौशल प्रदान करने में सक्षम नहीं है। इस वजह से उनमें रोजगार योग्यता की कमी है।

उपाय- शैक्षिक प्रयासों को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब छात्र सफल होने के बाद समाज में मूल्य पैदा करेंगे और मूल्य जोड़ेंगे और अपने संस्थानों में वापस योगदान देंगे या वैश्विक मानकों के नए संस्थान शुरू करेंगे। उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को ज्ञान विस्तार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा अपने पाठ्यक्रम को नियमित रूप से संशोधित करना चाहिए। महाविद्यालयों द्वारा कार्यशालाएं, संगोष्ठी, सम्मेलन, संगोष्ठी आयोजित की जानी चाहिए और शिक्षकों को उनके ज्ञान और कौशल के नियमित उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगाया जाना चाहिए। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रों से एक प्रतिक्रिया प्रणाली का भी उपयोग किया जाना चाहिए। संस्थागत विकास प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका का मूल्यांकन करें।

2. शिक्षा में निवेश- केंद्रीय बजट 2017-18 में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए शिक्षा क्षेत्र के लिए 79,685.95 करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया है। कुल व्यय में से 46,356.25 रुपये स्कूल क्षेत्र के लिए और शेष उच्च शिक्षा के लिए है। 2017-18 में उच्च शिक्षा के ई-लर्निंग पोर्टफोलियो के लिए कुल 497 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर खर्च का आकलन करते हैं, तो भारत अभी भी दुनिया के कुछ देशों से पीछे है। .

उपाय- निजी क्षेत्र शिक्षा में निवेश की खाई को पाटने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

3. छात्र-शिक्षक अनुपात - भारत में, छात्र-शिक्षक अनुपात दुनिया के अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। उदाहरण के लिए, विकसित देशों में यह अनुपात 11.4 है। जबकि भारत के मामले में यह 21.0 है जो काफी अधिक है। भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में फैकल्टी की कमी का सामना कर रहा है।

उपाय- नए शिक्षकों की भर्ती करने और प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कौशल और ज्ञान की गुणवत्ता को अद्यतन करने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

4. बुनियादी ढांचे का विकास- भारत आगामी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए पर्याप्त ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने में विफल रहा है। यह कम क्षमता उपयोग का एक मुख्य कारण है।

उपाय- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण भौतिक आधारभूत संरचना की स्थापना में गैर राजनीतिक निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है। इन बुनियादी सुविधाओं में कॉलेज की इमारत, पर्याप्त

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 8, August 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

पुस्तकालय, कक्षाओं और प्रस्तुति के संचालन के लिए विशाल कक्षाएं, फर्नीचर, लड़कों और लड़कियों के छात्रावास, परिवहन सुविधाएं, खेल सुविधाएं, वाणिज्यिक भवन, प्रयोगशालाएं आदि शामिल हैं।

5. विश्व से प्रतिस्पर्धा - भारत की उच्च शिक्षा की औसत गुणवत्ता विश्व औसत से धीरे-धीरे पीछे होती जा रही है। जरूरत इस बात की है कि दूसरे देशों में शिक्षा के विभिन्न-अलग-अलग सफल मॉडलों का अध्ययन किया जाए और हमारी शिक्षा प्रणाली में उनके सर्वोत्तम उपयुक्त मॉडल को लागू किया जाए।

उपाय- अन्य देशों के साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए, हमें अपने मानकों को बढ़ाने और नए मानक स्थापित करने की आवश्यकता है। यह उच्च शिक्षा प्रणाली को पर्याप्त उद्देश्य, पुनर्रचना आदि स्थापित करने के लिए लाभ प्रदान करेगा। हमें विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना पर ध्यान देना चाहिए, आर्थिक प्रगति में नेतृत्व करने के लिए संस्थानों में कुशल और व्यावहारिक शिक्षाविदों की भर्ती करनी चाहिए। युवा कार्यबल को मेहनती लोगों में परिवर्तित करना आवश्यक है और इसे पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्रदान करके प्राप्त किया जा सकता है। पुरानी तकनीकों को बदलने की जरूरत है जो पुरानी हैं और कम उत्पादन देती हैं। इस प्रतिस्पर्धी माहौल में बढ़त बनाने के लिए, हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए नई तकनीकों के प्रभावी उपयोग पर ध्यान देना चाहिए।

6. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल-सरकार पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं मुहैया कराने का बोझ है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सरकार के बोझ को कम करने के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

उपाय- उच्च शिक्षा संस्थानों और कॉर्पोरेट के बीच सहयोग से छात्रों को प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के माध्यम से औद्योगिक गतिविधियों का अनुभव प्राप्त करने, संयुक्त अनुसंधान और विकास, परियोजनाओं आदि का आयोजन करने में मदद मिलेगी। इससे छात्रों को अधिक रोजगार मिलेगा और इससे शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।

7. सस्ती शिक्षा - यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिले, हमें शिक्षा को वहनीय बनाना होगा। सरकार द्वारा प्रायोजित और स्वामित्व वाले संस्थानों में शुल्क संरचना भारत में कम लागत वाली और सस्ती है। लेकिन निजी संस्थानों में यह काफी अधिक है और गरीब छात्रों के लिए वहनीय नहीं है।

उपाय- इस समस्या के समाधान के लिए संस्थानों को यह ध्यान रखना होगा कि कोई भी योग्य छात्र सिर्फ उच्च शुल्क के कारण प्रवेश लेने में असमर्थ हो जाए। उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए।

8. विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों-भारत में सबसे ज्यादा नं. दुनिया में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या अभी भी भारतीय छात्र विदेशों में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करना पसंद करते हैं और नहीं। नामांकन में वृद्धि हो रही है। भारतीय छात्रों को विदेश में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करने वाले विभिन्न कारक हैं (ए) धन और आकांक्षाएं (बी) शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता (सी) अधिक उद्योग एक्सपोजर और प्राप्त अनुभव (डी) सामाजिक स्थिति।

उपाय- हमें अपने शिक्षण संस्थानों का निर्माण करते समय इन मुद्दों की पहचान करनी चाहिए ताकि इस प्रवृत्ति को बदला जा सके।

9. शिक्षा में नैतिकता - शिक्षा नैतिकता की बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भूमिका है। छात्रों द्वारा ऋण चुकौती के संबंध में एक खतरनाक प्रवृत्ति देखी जा सकती है। यदि छात्र शैक्षिक ऋण चुकाने में विफल रहते हैं, तो बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्ति बढ़ जाएगी और इसके कारण, बैंक शैक्षिक ऋण स्वीकृत करने में निंदक होंगे।

International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 8 Issue 8, August 2018,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gate as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

उपाय- शिक्षा ऋण की चूक को कम करने के लिए, छात्रों के कॉलेज के पूर्व छात्र संघ को सक्रिय रूप से छात्रों के बीच नैतिकता और मूल्यों को विकसित करना होगा। . छात्रों को एक अच्छा इंसान बनने में मदद करने के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली में नैतिकता को पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। छात्रों को नैतिकता और मूल्यों के साथ-साथ कौशल और ज्ञान से लैस किया जाना चाहिए।

10. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा - छात्र मूल्यांकन प्रणाली में सुधार पर जोर देने की आवश्यकता है। मौजूदा छात्र मूल्यांकन प्रणाली छात्रों द्वारा प्राप्त उत्कृष्टता की विभिन्न डिग्री का न्याय करने और छात्रों के बीच कौशल स्तर को बढ़ाने के लिए अपर्याप्त है।

उपाय- पारंपरिक व्याख्यान विधियों के बजाय, हमें शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को अधिक मूल्यवान, छात्र-उन्मुख, आकर्षक और गतिविधि उन्मुख बनाने के लिए केस स्टडी, समूह चर्चा, प्रस्तुतीकरण, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, सेमिनार, पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नोत्तरी आदि का भी उपयोग करना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वैज्ञानिक सक्रिय अधिगम के आधार पर नियोजित किया जाना चाहिए और छात्रों को चीजों के बारे में जिज्ञासा विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे छात्रों में आत्मविश्वास और सीखने का विकास होगा।

11. शिक्षक के प्रदर्शन की समीक्षा - न केवल छात्रों के प्रदर्शन बल्कि शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके अद्यतन विषय ज्ञान, पढ़ाने और प्रभावी ढंग से काम करने की क्षमता और छात्रों के लिए सलाहकार के रूप में कार्य करने के संदर्भ में किया जाना चाहिए। छात्रों के परिणामों में सुधार लाने और छात्र उपलब्धि में अंतराल को कम करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला शिक्षण महत्वपूर्ण है। शिक्षक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली शिक्षकों को महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रदान करती है जो पेशेवर सीखने और विकास को आश्वस्त करते हैं। शिक्षकों को विभागीय गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए ताकि कॉलेज सुधार योजनाओं में योगदान दिया जा सके।

उपाय- शिक्षकों के वैज्ञानिक मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। आपसी अनुभव साझा करने और मिलनसार माहौल बनाने में मदद करने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, इंट्रा कॉलेज और इंटर कॉलेज शिक्षकों के बीच अनुभव साझा करने वाले सत्र या गतिविधियाँ होनी चाहिए। यह सभी भाग लेने वाले शिक्षकों को सीखने का अनुभव प्रदान करेगा। प्रत्येक चरण में निगरानी और उपयुक्त परिमाणीकरण तकनीकों द्वारा प्रशिक्षण के बाद प्रदर्शन का मापन भी आवश्यक है।

12. प्रदर्शन समीक्षा/मूल्यांकन को मजबूत करना - किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को प्रेरित करने वाले पैरामीटर प्रवेश दर, प्लेसमेंट, कॉलेज की प्रतिष्ठा, अनुपस्थिति, छोड़ने की दर, छात्र अशांति, कॉलेज रैंकिंग, प्रवेश परीक्षा स्तर, पिछले परिणाम, उपन्यास और उन्नत शिक्षण पद्धति हैं। पुस्तकालय और बुनियादी ढांचा, शैक्षणिक निगरानी, विभिन्न छात्र विकास संघों का कार्य, छात्रों में रचनात्मक और तार्किक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियाँ आदि।

उपाय- प्रदर्शन की समीक्षा की जानी चाहिए। उन कारकों पर काम किया जाना चाहिए, जिनके खिलाफ छात्रों और शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाना है। अंतरिक्ष में छात्र, संकाय, विभाग और कॉलेज शामिल होंगे।

निष्कर्ष-

अध्ययन से पता चलता है कि उच्च शिक्षा प्रणाली समाज की बदलती जरूरतों का जवाब देने में सक्षम नहीं है। आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से विकासशील देशों में से एक है। उस विकास को बनाए रखने के लिए भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने की आवश्यकता है। भविष्य की आवश्यकताओं को प्राप्त

करने के लिए वित्तीय संसाधनों, पहुंच और इक्विटी, गुणवत्ता मानकों, प्रासंगिकता और अंत में उत्तरदायित्व का पुनर्विश्लेषण करने की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। डीपी सिंह, उपाध्यक्ष और प्रमुख एचआर, आईबीएम इंडिया/दक्षिण एशिया ने कहा, "कौशल वैश्विक स्तर पर और भारत में व्यवसायों में नई मुद्रा के रूप में उभर रहा है। आज का तेजी से विकसित हो रहा आर्थिक माहौल जॉब प्रोफाइल और क्षेत्रों में अप-स्किलिंग को अनिवार्य बना देता है। भारत एक कौशल अंतर और एक उच्च शिक्षा क्षेत्र दोनों को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। यही कारण है कि उच्च शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए सक्रिय उपाय करना महत्वपूर्ण है ताकि एक नया मॉडल तैयार किया जा सके जो उद्योग की अनिवार्यताओं के साथ बेहतर संरेखित हो। " तकनीकी प्रगति, लगातार बदलती कौशल आवश्यकताओं और अप्रचलित पाठ्यक्रम भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए छात्रों को रोजगार योग्यता कौशल से लैस करने के प्रयासों में चुनौतियां हैं। भारत को उद्योग के साथ साझेदारी करके छात्रों को आवश्यक कौशल प्रदान करने पर विचार करना चाहिए, गुणवत्ता और बेहतर उत्पादन के लिए नई शिक्षण तकनीकों को अपनाना चाहिए और अनुभव-आधारित, व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना।

References –

1. Singh J.D.,Higher Education in India – Issues, Challengesand Suggestions (2011),'Higher Education', LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2011, Pp.93-103. ISBN: 978-3-8465-1753-6
2. P. Arunachalam,Higher Education Sector in India: Issues and Imperatives (2010) Journal of Global Economy, Volume 6 No 4, JULY-AUGUST, 2010.
3. ChahalMukesh, Higher Education in India: Emerging Issues,Challenges and Suggestions (2015), International journal of business quantitative and economics and applied management research, ISSN: 2349-5677Volume 1, Issue 11, April 2015.
4. KonwarNitu, ChakrabortySubhadeep, Status of Higher Education in Rural Areas of india (2013),Journal of Radix International Educational and Research Consortium, ISSN: 2250 – 3994, Volume 2, Issue 1 (January 2013)
5. Bhattacharya Jonaki and Pal Prasenjit, Higher Education in India: Recent Issues and Trends (2016), Research Journal of Educational Sciences , ISSN 2321-0508, Vol. 4(1), 10-16, January (2016)
6. KumariNeeraj,An analytical study of parameters affecting quality of undergraduate engineering programmes in Haryana (2014)
7. Report of the All India Survey on Higher education (AISHE) - (2015-16) by Govt. of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education.